फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 234 प्रभात जयपुर, रविवार 29 मार्च, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Did Rajasthan Royals Get Their True Value??

Former BCCI treasurer Kishore Rungta described the deal as 'good, bad and ugly.' The prices may look expensive as was in the beginning when the IPL started

Union Football Club Jaipur Celebrates Sthapana Divas

'भाजपा मध्य प्रदेश-राजस्थान जैसा प्रयोग बिहार में ना दोहराए'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आग्रह है कि उनका उत्तराधिकारी मध्य प्रदेश-राजस्थान की तरह कोई लो प्रोफाइल नेता नहीं होना चाहिए

- भाजपा को उम्मीद थी कि 26 मार्च को समृद्धि यात्रा खत्म होने के साथ नीतीश मुख्यमंत्री पद त्याग कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। असल में नीतीश चाहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में उन्हें पूरी तरह से भरोसे में लिया जाए।
- जद (यू) सूत्रों ने कहा, नीतीश ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी ऐसा हो जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके, वे ऐसा उत्तराधिकारी चाहते हैं, जो नीतीश व उनके बेटे निशांत को भी भरोसे में ले और समाजवादी सोच रखता हो, क्योंकि मध्य प्रदेश व राजस्थान के विपरीत बिहार में समाजवाद की जड़ें गहरी हैं।
- जद (यू) यह भी चाहता है कि एनडीए के छोटे घटक दलों को भी भरोसे में लिया जाए।
- सूत्रों ने कहा, अगर जद (यू) को जूनियर पार्टनर माना गया तो पार्टी विधानसभा स्पीकर की पोस्ट पर दावा करेगी। पार्टी चाहती है कि किसी को भी यह न लगे कि नीतीश के राज्यसभा में जाने के बाद पार्टी कमज़ोर हो गई है, यही नहीं अब कुमार बिहार को ज्यादा समय देंगे।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाजपा उनके उत्तराधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रयोग को न दोहराए, जिसमें लो प्रोफाइल नेताओं को आगे बढ़ाया गया था।

भाजपा को उम्मीद थी कि कुमार अपनी "समृद्धि यात्रा" के अंत में पद छोड़ देंगे, जो 26 मार्च को खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि वे चाहते हैं कि उत्तराधिकारी के चयन में भाजपा उन्हें "पूरी तरह विश्वास में" ले।

मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों को लेकर अटकलें जारी हैं, लेकिन जदयू के सूत्रों का कहना है कि पद छोड़ रहे मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके और उनकी राजनीति के तौर-तरीकों के अनुसार काम कर सके। एक जदयू नेता ने कहा, "हम नहीं चाहते कि सरकार का सामाजिक संतुलन बिगड़े। हम ऐसा नेता भी चाहते हैं जो कुमार के बेटे निशांत को भी विश्वास में ले सके।" नेता ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के विपरीत, बिहार में समाजवादी सोच की जड़ें बहुत गहरी हैं।

ऐसी खबरें हैं कि जदयू इस बात पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल के पूर्व प्र.मंत्री ओली तथा गृहमंत्री लेखक गिरफ्तार

काठमांडू, 28 मार्च। नेपाल में बालेन्द्र सरकार शपथ ग्रहण के साथ पहले ही दिन से एक्शन में आ गई है। शपथग्रहण को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि जैन ज़ी प्रदर्शन के दौरान निहत्थे छात्रों की हत्या के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया।

बालेन्द्र की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक ने जैन ज़ी आंदोलन की जांच के लिए गठित आयोग के सिफारिश को लागू करने का फैसला किया। आज सुबह सूरज निकलने पर पहले तो गृहमंत्री रमेश लेखक और बाद में पूर्व प्रधानमंत्री ओली की गिरफ्तारी हुई।

- नेपाल में शपथ ग्रहण के साथ ही बालेन्द्र सरकार एक्शन में आ गई, और जैन ज़ी छात्रों के प्रदर्शन पर बल प्रयोग के लिए पूर्व प्र.मंत्री ओली तथा गृहमंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के आदेश दिए।

जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओली और लेखक के साथ पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना के अधिकारियों को भी दोषी ठहराया है, लेकिन सुरक्षा बलों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं लेने का निर्णय लिया गया। सरकार ने एक समिति बनाकर इनकी भूमिका की जांच कराने का फैसला किया है।

'मोदी-ट्रंप वार्ता में मस्क मौजूद नहीं थे'

भारतीय विदेश मंत्रालय ने वार्ता में मस्क की मौजूदगी संबंधी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट खारिज कर दी

- न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का कहना था कि ट्रंप और मस्क में फिर से दोस्ती हो गई है और मोदी और ट्रंप की टेलीफोन पर हुई वार्ता में मस्क भी शामिल थे। दो राष्ट्राध्यक्षों की वार्ता में एक नागरिक के शामिल होने को लेकर भारत में भारी विवाद हुआ।
- ज्ञातव्य है कि ट्रंप व एलन मस्क की दोस्ती में गत दिनों भारी दरार आ गई थी, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी की थी।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। भारत ने उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि ईरान युद्ध पर चर्चा के लिए मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई फोन बातचीत में स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क भी शामिल थे।

"न्यूयॉर्क टाइम्स" की एक रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई इस टेलीफोनिक बातचीत में हिस्सा लिया था, जिसे ट्रंप और मस्क के बीच की अनबन के खत्म होने का संकेत माना गया। ट्रंप के बड़े प्रशंसक, फंडिंग करने वाले और समर्थक रहे स्पेसएक्स के संस्थापक का कुछ महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से मतभेद हो गया था। जो भी हो, ट्रंप-मोदी वार्ता में एक सामान्य नागरिक की मौजूदगी ने भारत में विवाद खड़ा कर दिया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि 24 मार्च की बातचीत केवल ट्रंप और मोदी के बीच ही हुई थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि वार्ता का केन्द्र पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति रही, जिसमें दोनों नेताओं ने होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने, सुरक्षित और सुलभ बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रपति ट्रंप का यह फोन उस घोषणा के बाद आया, जिसमें उन्होंने ईरान के ठिकानों पर सैन्य हमलों को पांच दिन के लिए टालने की बात कही थी, जिससे संघर्ष के जल्द समाप्त होने की उम्मीदें बढ़ी हैं। इसी दौरान ऐसी खबरें भी आई हैं कि वॉशिंगटन ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजने पर विचार कर रहा है।

24 मार्च की ट्रंप-मोदी बातचीत फरवरी के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई पहली बातचीत थी, जब ट्रंप ने व्यापार समझौते और भारत पर टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: "राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर उपयोगी विचार-विमर्श हुआ।

भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहे।"

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज़ स्ट्रेट से निर्बाध परिवहन वैश्विक शांति, स्थिरता और आर्थिक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ईरान ने अब सऊदी अरब, कुवैत में अमेरिका की सुविधाओं पर सीधे बमबारी शुरु की

ईरान व हिजबुल्लाह ने नया नारा भी दिया है कि उनका ध्येय अब अमेरिका को खाड़ी देशों की मुस्लिम भूमि से बाहर निकालना है

- ईरान का संरक्षण प्राप्त, यमनवासी हूती विद्रोहियों ने "रैड सी" से पर्शियन खाड़ी क्षेत्र में जहाजों का आना एक बार पहले बंद कर दिया था और अब दोबारा समुद्री जहाजों का आवागमन पुनः बंद करने की धमकी दी है।
- इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी अस्त-व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर माल पानी के जहाजों से आता जाता है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के ईरान के साथ शांति वार्ता के दावों को झूठा साबित करते हुए, पश्चिम एशिया का संकट और अधिक फैलने के कगार पर है। ईरान अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर रहा है, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ रही है। इज़रायल और हिज़्बुल्लाह के बीच टकराव भी लगातार ज्यादा खूनी होता जा रहा है।

ईरान और हिज़्बुल्लाह ने अब एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका खुला लक्ष्य मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों से अमेरिकियों को बाहर निकालना है। इससे पूरे मध्य पूर्व में "लोन वुल्फ" (अकेले काम करने वाले) आतंकियों के साथ-साथ, पश्चिमी देशों में ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क भी प्रेरित हो रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की

नई दिल्ली, 28 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत कर पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण स्थिति पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुताबिक बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय ऊर्जा ठांचों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई।

- प्र.मंत्री मोदी ने एक्स पर इस फोन वार्ता की जानकारी दी और कहा कि पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वॉशिंगटन की राजनीति में भारी भूचाल?

ट्रंप को दरकिनार करने की मांग ने जोर पकड़ा

- एक बहुप्रतिष्ठित "कंज़र्वेटिव" नेता ने सार्वजनिक तौर पर उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस का आह्वान किया कि वे संविधान के पच्चीसवें संशोधन का उपयोग करके, राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता से हटाने की कवायद शुरु करें।
- हालांकि, यह प्रक्रिया काफी जटिल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के दो तिहाई सदस्यों को साथ में लेकर यह घोषित करना होगा कि राष्ट्रपति अब अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हैं। अगर इस मांग को चुनौती दी जाती है तो मामला "कांग्रेस" तक पहुँचेगा तथा वहाँ दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत का समर्थन पाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- वर्तमान पृष्ठभूमि में, पच्चीसवां संशोधन अब संवैधानिक व्यवस्था के बारे में केवल एक तर्क नहीं रह गया है, बल्कि एक राजनीतिक स्टेटमैंट बन गया है, वर्तमान प्रशासन के खिलाफ फैलते असंतोष के रूप में।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। अमेरिकी राजनीति में गहराती उथल-पुथल को दर्शाने वाले एक असाधारण घटनाक्रम में, एक प्रमुख कंज़र्वेटिव नेता ने सार्वजनिक रूप से उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से कहा है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए 25वें संशोधन को लागू करने पर विचार करें। इस सुझाव ने वॉशिंगटन के राजनीतिक तंत्र और रिपब्लिकन खेमे, दोनों में खलबली मचा दी है।

यह बिना मांगी सलाह है जो राजनीति रूप से असाधारण तो है ही साथ ही असहमति का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह सुझाव ट्रंप के विरोधियों की ओर से नहीं, बल्कि व्यापक कंज़र्वेटिव समूह के भीतर से सामने आया है। हालांकि व्यक्ति की पहचान और प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इससे भी अधिक अहम यह है कि 25वां संशोधन, जिसे लंबे समय से अंतिम संवैधानिक उपाय के रूप में देखा जाता रहा है, एक बार फिर मुख्यधारा की राजनीतिक चर्चा में आ गया है।

मूल रूप से, 25वां संशोधन राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या अक्षमता की स्थिति में सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान करता है। इसका सबसे विवादास्पद प्रावधान, धारा 4, उपराष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के बहुमत के साथ मिलकर यह घोषित करने की अनुमति देता है कि वर्तमान राष्ट्रपति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)